आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 16 अंक : 40 लखनऊ, बुद्धवार 28 जनवरी 2026 स 06 फरवरी 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

यूजीसी के नए नियमों पर शिक्षा मंत्री का आश्वासः ‘संविधान के दायरे में होगी व्यवस्था, नहीं होगा किसी के साथ भेदभाव’

नई दिल्ली। यूजीसी के नए नियमों को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं होगा। किसी के साथ भेदभाव या अत्याचार के लिए इन प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के तय दायित्व की भी बात कही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि वह सभी को आश्वस्त करते हैं कि किसी से भी भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में आई है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कई नेताओं व संगठनों ने संशय व्यक्त किया है। इस संशय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि वह सभी को आश्वस्त करते हैं कि किसी से भी भेदभाव नहीं होगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह बनाना है। वहीं यूजीसी का मानना है कि नए नियमों का मकसद शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाना और सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करना है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ग, समुदाय या व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। यूजीसी के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के लागू होने से किसी का उत्पीड़न नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के हित सर्वोपरि रहेंगे और सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए संवाद का रास्ता खुला रहेगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यूजीसी के इन नियमों को लेकर प्रश्न पूछे गए। मंगलवार को उनसे पूछा गया कि यह पूरा मामला क्या है। क्या लोग इस मामले को समझ ही नहीं पा रहे हैं या फिर जानबूझकर विवाद बनाया जा रहा है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह पूरी विनम्रता के साथ सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भेदभाव के नाम पर किसी को भी इसका अनुचित इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसमें उनका दायित्व रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि वह आश्वस्त करते हैं कि जो व्यवस्था हुई है, भारत की जो भी व्यवस्था हो, वह संविधान की परिधि के अंदर होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जो विषय आया है, यह तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यह भी दोहराया कि किसी पर भी अत्याचार नहीं होगा। दरअसल यूजीसी के नए नियमों का लगातार विरोध हो रहा है। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसका विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इन नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों के उत्पीड़न या शिकायत को शामिल नहीं किया गया है। यानी केवल पिछड़े वर्गों के छात्रों की शिकायत पर ही कार्रवाई होगी। शिकायत गलत पाए जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १३ जनवरी को श्प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन २०२६श लागू किया। इसके तहत कई संस्थानों को इक्विटी कमेटी बनाने और भेदभाव विरोधी नीति लागू करने के निर्देश दिए गए। यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक हलवा समारोह में लिया भाग, अंतिम चरण में बजट की तैयारी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया। यह एक फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले आम बजट २०२६–२७ की तैयारी के अंतिम चरण का प्रतीक है। यह समारोह रायसीना हिल्स स्थित नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित किया गया, जो वित्त मंत्रालय का पुराना पता है। गौरतलब है कि कर्तव्य भवन–१ स्थित नए परिसर में छापाखाना नहीं है। वित्त मंत्री और उनकी टीम के अधिकतर सदस्य सितंबर २०२५ में प्रतिष्ठित और भव्य नॉर्थ ब्लॉक से कर्तव्य भवन स्थित आधुनिक केंद्रीय सचिवालय कार्यालय में स्थानांतरित हो गए थे यह बजट से पहले होने वाला सालाना समारोह है, जिसमें पारंपरिक मिठाई ‘हलवा’ तैयार की जाती है और वित्त मंत्रालय के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसी जाती है जो बजट तैयार करने के काम में शामिल होते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हलवा समारोह आम बजट तैयार करने में शामिल अधिकारियों के बाकी लोगों से अलग होने की प्रक्रिया से ठीक पहले होता है। परंपरा को बरकरार रखते हुए इसका आयोजन नॉर्थ ब्लॉक के भूतल में किया गया, जिसमें वित्त मंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। समारोह के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा भी किया और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही पूरी बजट टीम को अपनी शुभकामनाएं दीं। हलवा समारोह में वित्त मंत्री के साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सभी विभागों के सचिव और बजट तैयारी में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पिछले पांच पूर्ण केंद्रीय बजट और एक अंतरिम बजट की तरह, २०२६–२७ का पूर्ण केंद्रीय बजट भी कागज रहित यानी डिजिटल रूप में होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे बजट के रूप में जाना जाता है) अनुदान मांगें, वित्त विधेयक आदि सहित केंद्रीय बजट के सभी दस्तावेज ‘केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप’ पर उपलब्ध होंगे। दरअसल ‘हलवा’ समारोह केंद्र सरकार के बजट की तैयारी में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘अलग रखने’ की प्रक्रिया है। यानी बाहर की दुनिया से वे पूरी तरह अलग–थलग होते हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी संसद में बजट पेश होने तक नॉर्थ ब्लॉक के ‘बेसमेंट’ में ही रहते हैं। जहां पूरी गोपनीयता रखी जाती है। वित्त मंत्री के लोकसभा में अपना बजट भाषण पूरा करने के बाद ही वे बाहर आते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक ऐतिहासिक छलांगः सीएम योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक ऐतिहासिक छलांग है। आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर कहा,‘माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक यात्रा में एक ऐतिहासिक छलांग है। यह रणनीतिक समझौता भारत को २७ यूरोपीय देशों के साथ जोड़ता है और ९९ प्रतिशत से अधिक भारतीय सामानों के लिए तरजीही बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे लगभग ६.४१ लाख करोड़ रुपये की निर्यात क्षमता खुलती है, खासकर श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए।’ उन्होंने कहा, ‘किसानों को सशक्त बनाकर, एमएसएमई को मजबूत करके, विनिर्माण और सेवाओं को बढ़ावा देकर, और कुशल पेशेवरों के लिए अवसरों का विस्तार करके, यह समझौता साझा समृद्धि और एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक खाका बन जाता है।’ भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए जिसे ‘अबतक का सबसे बड़ा समझौता’ बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व ने व्यापार एवं रक्षा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने और नियम–आधारित विश्व व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए एक व्यापक एजेंडा पेश किया।

सम्पादकीय

न्यायपालिका की साखः तबादलों के खेल में सिसकती स्वतंत्रता

भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभों में न्यायपालिका को सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके पास जन–विश्वास की वह पूंजी है, जो कार्यपालिका या विधायिका के पास अक्सर कम होती है। लेकिन हाल के दिनों में उच्च और निचली अदालतों के जजों के ‘विवादित’ तबादलों ने इस भरोसे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्जल भूइंया की हालिया टिप्पणी ने उसी कड़वे सच से पर्दा उठाया है जिसे अक्सर न्यायिक गलियारों में दबा दिया जाता है। न्यायमूर्ति भूइंया ने एक बुनियादी सवाल उठाया हैरू क्या किसी जज का तबादला सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि उसने सरकार के लिए कोई ‘असुविधाजनक निर्णय’ दिया है? यद्यपि उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर जस्टिस अतुल श्रीधरन की ओर था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस श्रीधरन ने जब एक मंत्री के बयान पर कड़ा रुख अपनाया, तो क लेजियम के फैसलों में केंद्र के ‘अनुरोध’ की दखलअंदाजी साफ दिखी। उन्हें छत्तीसगढ़ के बजाय इलाहाबाद भेजा जाना महज प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक संदेश की तरह लगा। जब उच्चतर न्यायपालिका में तबादलों के पीछे राजनीतिक पटकथा लिखी जाने लगे, तो निचली अदालतों के जजों का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (**CJM**) विभांशु सुधीर का मामला इसका ज्वलंत उदाहरण है। संभल हिंसा मामले में पुलिस अधिकारी पर मामला दर्ज करने का साहस दिखाने के कुछ ही दिनों भीतर उनका तबादला हो जाना, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया पर गहरा आघात है। यह स्थिति जजों के मन में भय पैदा करती हैं ‘न्याय करो, लेकिन सत्ता की कीमत पर नहीं।’ न्यायमूर्ति भूइंया की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने सही कहा कि न्यायपालिका के पास न तो ‘धन’ है और न शतलवारश्य उसकी एकमात्र ताकत जनता का भरोसा है। यदि न्यायाधीशों के फैसले कानून के बजाय तबादलों के डर से प्रभावित होने लगेंगे, तो अदालतें महज ईंट–पत्थर की इमारतें बनकर रह जाएंगी। जैसा कि न्यायमूर्ति ने कहा, ऐसी स्थिति में षदिल और आत्माष का लोप हो जाएगा। न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों में पारदर्शिता की कमी न केवल न्यायपालिका की साख को बट्टा लगा रही है, बल्कि पूरी शासन व्यवस्था के औचित्य को भी संदिग्ध कर रही है। कॉलेजियम को अपनी स्वायत्तता की रक्षा करनी होगी और कार्यपालिका को लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना होगा। यदि न्याय का मंदिर ही राजनीतिक हस्तक्षेप की भेंट चढ़ गया, तो आम आदमी के पास आखिरी उम्मीद का कोई दरवाजा नहीं बचेगा।

सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा, संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं: अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी भाजपा संविधान को अपने से नीचे समझने की भूल कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जनता आज यह सवाल कर रही है कि जब अपने ऊपर दर्ज मुकदमे हटवाए गए, तब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कार्य किया गया। मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोग लगातार मंचों से ‘सनातनी संतों’ का तिरस्कार कर रहे हैं और अपमानजनक उपमाओं का प्रयोग कर समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि माघ मेले जैसे पवित्र आयोजन में भी नकारात्मक ‘बुलडोजरी सोच’ के समर्थन में नारे लगवाकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जबकि उपद्रव करने वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ताकामी भाजपा का धर्म–विरोधी चेहरा अब पूरी तरह बेनकघब हो चुका है। जो नुकसान होना था, वह हो चुका है और अब मजबूरी में मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि माफी वही मायने रखती है, जो दिल से मांगी जाए। अखिलेश यादव ने शासनाधीशों को आगाह करते हुए कहा कि हठ हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का विचार, वक्तव्य और व्यवहार लगातार असंवैधानिक रहा है। सत्ता के नशे में चूर संविधान–विरोधी भाजपा अब जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है।

उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ राज्य की छवि को पीछे छोड़ते हुए आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत संबल बन रहा है। :सीएम योगी

लखनऊ/मथुरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ राज्य की छवि को पीछे छोड़ते हुए आज भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत संबल बन रहा है। मथुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर हार्दिक स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि नितिन नवीन का (पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद) पहला दौरा योगेश्वर श्रीकृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा में हुआ है। उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश की जनता और राज्यभर के भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं।’ मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन को युवा ऊर्जा और संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के पाटलिपुत्र से पांच बार विधायक रह चुके नवीन ने भाजपा में विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्र–वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव और बलदेव सदियों से सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा के केंद्र रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘इस भूमि का हर कण श्रीकृष्ण और राधा रानी की आध्यात्मिक विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है।’ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह जिला भाजपा के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि होने के कारण भी विशेष महत्व रखता है। ‘डबल इंजन’ सरकार के तहत हुए विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘‘बीमारू’’ राज्य नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘सरकार ने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की है और बिना किसी भेदभाव के कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, जिससे किसान, युवा, महिलाएं और गरीब समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए गांवों से लेकर शहरों तक विकास कार्य प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं। राज्य की बदली छवि पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था और उसकी विरासत का उपहास उड़ाया जाता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आज वही उत्तर प्रदेश भारत के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जिसमें युवा, किसान और महिलाएं सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में विकास को नयी गति देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर ने दिया इस्तीफा : अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा– ‘ये अधिकारी चापलूसी कर रहा’

लखनऊ। अयोध्या के **GST** डिप्टी कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अपना इस्तीफ सौंप दिया है। इस पर सीएम योगी के पक्ष में इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने चापलूस बताया। शंकराचार्य ने कहा कि यह अधिकारी चापलूसी कर रहा है। इस अधिकारी का इस्तीफा भी तत्काल प्रभाव से मंजूर किया जाए नहीं तो हम समझेंगे कि ये इनके बीच का है। शंकराचार्य ने कहा कि मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा यूजीसी को लेकर भी बोले कि ये फैसला विभाजित करने वाला है। बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह ने अपना दो पन्नों का इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। अपने बयान में प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठा रहे हैं। उनका कहना है कि शंकराचार्य द्वारा सीएम योगी पर की गई अभद्र टिप्पणी से वह गहरे आहत थे। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा, श्जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, जिस प्रदेश से मुझे सैलरी मिलती है, मैं उसका पक्षधर हूंष सीएम योगी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।श उन्होंने बताया कि पिछले तीन दिनों से वह मानसिक रूप से व्यथित थे। साथ ही कहा कि जब उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो वह अपने निजी संसाधनों से सामाजिक कार्यों में जुट जाएंगे। बता दें प्रशांत सिंह ने अपने पत्र में लिखा, कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार व सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अविमुक्तेश्वरानन्द शंकराचार्य द्वारा किये गये अभद्र टिप्पणी से मैं आहत हूं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश राज्य का एक साधारण कर्मचारी हूं। उत्तर प्रदेश सरकार से हमें आजीविका प्राप्त है। उस आजीविका से मेरे परिवार का लालन पालन होता है तो मेरा राजकीय धर्म है कि अपने प्रदेश सरकार व सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध यदि कोई अनर्गल प्रलाप होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली का पालन करते हुए उसका विरोध किया जाये। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध अविमुक्तेश्वरानन्द शंकराचार्य द्वारा किये गये अभद्र टिप्पणी को राज्य, संविधान व लोकतंत्र के विरुद्ध मानता हूं। अतः ऐसी स्थिति में सरकार के पक्ष में और अविमुक्तेश्वरानन्द शंकराचार्य के विरोध में मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूं।

जिम की आड़ में धर्मांतरण गिरोह चलाने वाला गिरफ्तार

मिर्जापुर। जिले में जिम के जरिये महिलाओं के यौन शोषण, धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का एक संगठित गिरोह चलाने वाले सरगना को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मिर्जापुर के इमरान के रूप में की गयी है, वह अपने परिवार के साथ विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार मिर्जापुर जिले में केजीएम जिम वन नाम से इमरान के कई जिम हैं। पुलिस ने बताया कि वह अपने रिश्तेदारों द्वारा संचालित जिमों के माध्यम से यह गिरोह चलाता था। पुलिस के मुताबिक, वह अपने परिवार के साथ दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल ३ से दुबई भागने की कोशिश कर रहा था। केंद्र सरकार के आव्रजन विभाग ने उसे पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। मिर्जापुर एसएसपीध्डीआईजी सोमेन बर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ इमरान इस संगठित गिरोह का मुख्य सरगना था, और हमें सूचना मिली थी कि वह देश से भागने की कोशिश कर रहा था।

यूजीसी नियमों पर भड़का सवर्ण समाजः यूपी के विभिन्न जनपदों में विरोध–प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने लगाए सरकार विरोधी नारे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, संभल, कुशीनगर और अन्य जिलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के खिलाफ विरोध–प्रदर्शन हुए, जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया। अलीगढ़ में, छात्र प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट में हाथरस के भारतीय जनता पार्टी सांसद अनूप प्रधान के काफिले को रोक दिया और नए यूजीसी नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस विरोध–प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सदस्यों ने किया और इसे क्षत्रिय महासभा, अलीगढ़ के नेताओं का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी का पुतला भी जलाया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने नियमों को रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बाद में, प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। सोमवार को, प्रदर्शनकारियों के इसी समूह ने अलीगढ़ प्रदर्शनी मैदान में 'हिंदू विराट सम्मेलन' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बाधा डाली, जहां उपदेशक साध्वी प्राची मुख्य अतिथि थीं। वहीं, संभल के चंदौसी में 'ब्राह्मण शक्ति संघ' के सदस्यों ने फव्वारा चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और 'काला कानून वापस लो' जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने नियमों में संशोधन या उन्हें पूरी तरह से वापस लेने की मांग की, साथ ही राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। कुशीनगर में, 'अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन' के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यूजीसी के नियम शिक्षा में योग्यता और समानता को कमजोर करते हैं। अधिकारियों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे। उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए १३ जनवरी, २०२६ को प्रकाशित यूजीसी के नियमों में विशेष समितियों, हेल्पलाइन और निगरानी दलों की स्थापना अनिवार्य की गई है ताकि विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा स्थित सूरजपुर थाना क्षेत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय का मंगलवार को करणी सेना तथा विभिन्न किसान संगठन सहित अन्य संगठनों के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के विरुद्ध विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। यूजीसी के नए नियम जारी होने से क्षेत्र में कई संस्थानों संगठनों द्वारा विवाद तेज हो गया है। करणी सेना के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन में विभिन्न किसान संगठन और सवर्ण संगठन भी प्रमुख रूप से शामिल रहे। संगठनों द्वारा पैदल मार्च के दौरान कई जगह यातायात प्रभावित रहा जिसे यातायात पुलिस द्वारा सुचारू रूप से संचालित किया गया और प्रदर्शन कर रहे संगठन कार्यकर्ताओं को एक पंक्ति अनुसार कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचने के लिए मार्ग सुनिश्चित किया गया। कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी दिनों में प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त किया और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त कराया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में यूजीसी रिफॉर्म–२०२६ के विरोध में मंगलवार को सवर्ण आर्मी के बैनर तले सवर्ण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जुलूस निकालते हुए विभिन्न मार्गों से कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रिफॉर्म–२०२६ को 'काला कानून' बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि यह सुधार सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुजीत सिंह ने सरकार और सवर्ण समाज के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता इस मुद्दे पर विरोध दर्ज नहीं करा रहे हैं, उन्हें समाज जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई और केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ।

UP में कई जगह प्रदर्शन
UGC PROTEST 2026
स्वर्ण समाज संघर्ष समिति
UGC काला कानून वापस लो
भाजपा सरकार होश में आओ
आयोग
COMMISSION

बैंककर्मियों की हड़ताल से लखनऊ में २५०० करोड़ की क्लियरिंग प्रभावित

लखनऊ। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को हुई राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का असर लखनऊ में भी व्यापक रूप से देखने को मिला। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ६०५ शाखाओं के कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से शहर में २५०० करोड़ रुपये की क्लियरिंग प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। इसी क्रम में लखनऊ के इंडियन बैंक, हजरतगंज पर बैंककर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखीं। फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि हड़ताल से पहले बैंककर्मियों ने कई चरणों में धरना–प्रदर्शन, रैली और सोशल मीडिया अभियान चलाया, लेकिन केंद्र सरकार उनकी एकमात्र मांग पर विचार को तैयार नहीं है। सभा को संबोधित करते हुए एनसीबीई के महामंत्री कॉमरेड डी.के. सिंह ने कहा कि जब रिजर्व बैंक, एलआईसी, सेबी, नाबार्ड, एनपीसीआई और अनेक सरकारी विभागों में पांच कार्यदिवस लागू हो सकते हैं तो बैंकों में क्यों नहीं। कॉमरेड आर.एन. शुक्ला ने कहा कि कर्मचारी माह के शेष शनिवारों के अवकाश के बदले प्रतिदिन ४० मिनट अतिरिक्त कार्य करने को भी तैयार हैं। कॉमरेड एस.के. संगतानी ने सरकार की हठधर्मिता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) बैंककर्मियों की मांग स्वीकार कर सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेज चुका है, बावजूद इसके अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कॉमरेड मनमोहन दास ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग कोई भीख नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार है, जिसके लिए लंबी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। सभा को लक्ष्मण सिंह, शकील अहमद, संदीप सिंह, वी.के. माथुर, बी.डी. पांडे, एस.डी. मिश्रा, विभाकर कुशवाहा, आनंद सिंह, विशाखा वर्मा और स्वाति सिंह सहित कई बैंक नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि हड़ताल से आमजन को होने वाली असुविधा की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि हड़ताल के चलते लखनऊ में बैंकिंग सेवाएं लगभग ठप रहीं और व्यापक स्तर पर लेन–देन प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया कि हड़ताल के चलते लखनऊ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ६०५ शाखाओं के करीब १६ हजार कर्मचारी एवं अधिकारी हड़ताल पर रहे। अनुमान के अनुसार शहर में लगभग २५०० करोड़ रुपये की क्लियरिंग प्रभावित हुई।

प्रदेश में १२.५५ करोड़ से अधिक मतदाता सूची में शामिलः नवदीप रिणवा

लखनऊ। उप्र. में १६वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उप्र. के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम "मेरा भारत, मेरा वोट" है। साथ ही कहा कि २२ वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ६ जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची में १२ करोड़ ५५ लाख ५६ हजार २५ मतदाता शामिल किए गए हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को संपन्न कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप्र. ने मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक सहभागिता पर जोर दिया। किसी मतदाता का नाम गलती से न छूट जाए इसके लिए उन्होंने बताया कि अभी भी महिलाओं और १८ से २० वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवदीप रिणवा ने बताया कि बीते ११ और १८ जनवरी को चलाए गए अभियानों में ७ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि ३१ जनवरी को पुनः विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सीईओ यूपी की वेबसाइट, ईसीआई नेट ऐप या अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची में नाम अवश्य जांच लें। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, राज्य स्वीप आइकन सुधा सिंह व अनुष्का चौबे तथा जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में करीब ५०० अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में महिला और युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ७५ बीएलओ, ७५ बीएलओ सुपरवाइजर, १८ ईआरओ और ६ जिला निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा १८ वर्ष पूर्ण करने वाले १५ नए मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड प्रदान किए गए तथा पांच महिला मतदाताओं को विशेष सम्मान दिया गया।

फरवरी २०२६ तक तैयार होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट फेज–३ में भी तेजी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी तक ५६४ किमी लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इससे कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने –जेवर एयरपोर्ट फेज–३ के लिए भूमि अधिग्रहण तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि यूपी एयर कार्गो हब बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फरवरी २०२६ के अंत तक इसका निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि ५६४ किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश की कनेक्टिविटी को ऐतिहासिक मजबूती देगा और औद्योगिक, कृषि वॉल जिस्टिक्स गतिविधियों के लिए मजबूत आधार बनेगा। बैठक में बताया गया कि यह एक्सप्रेसवे १२ जनपदों से होकर गुजरता है और ५०० से अधिक गांवों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने सड़क गुणवत्ता के लिए रफनेस इंडेक्स और राइडिंग कम्फर्ट इंडेक्स जैसे आधुनिक तकनीकी मानकों के आधार पर परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही वे–साइड अमेनिटीज, रेस्ट एरिया, रोड सेफ्टी फीचर्स, साइनेज और एक्सेस–कंट्रोल सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर जोर दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने फेज–३ के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की वैश्विक कनेक्टिविटी का प्रवेश द्वार बनेगा और इसके संचालन से प्रदेश एयर कार्गो हब के रूप में नई पहचान हासिल करेगा। बैठक में बताया गया कि एयरपोर्ट के प्रथम चरण से प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ग्रेटर नोएडा में मल्टीमडल लजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से उद्योगों की लागत घटेगी और यूपी मैन्युफैक्चरिंग व सप्लाई– चेन का प्रमुख केंद्र बनेगा। चिल्ला एलिवेटेड फ्लाईओवर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थनगर संतकबीरनगर रेल लाइन परियोजनाओं में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। रिहंद और ओबरा क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा को औद्योगिक विकास की कुंजी बताया। मध्य गंगा नहर परियोजना (स्टेज–२) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि का प्रभावी माध्यम हैं। इस परियोजना से अमरोहा, मुरादाबाद और संभल के बड़े कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं एरच सिंचाई परियोजना से बुंदेलखंड में जल संरक्षण, सिंचाई और पेयजल उपलब्धता को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपूर्ण कार्य तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना की समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश के ७५ जिलों में १५० मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इनमें आधुनिक कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, डिजिटल लर्निंग, खेल और सह–शैक्षिक गतिविधियों की समुचित सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने भूमि चयन और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश न केवल देश का ग्रोथ इंजन बनेगा, बल्कि वैश्विक निवेश मानचित्र पर भी मजबूत पहचान स्थापित करेगा।

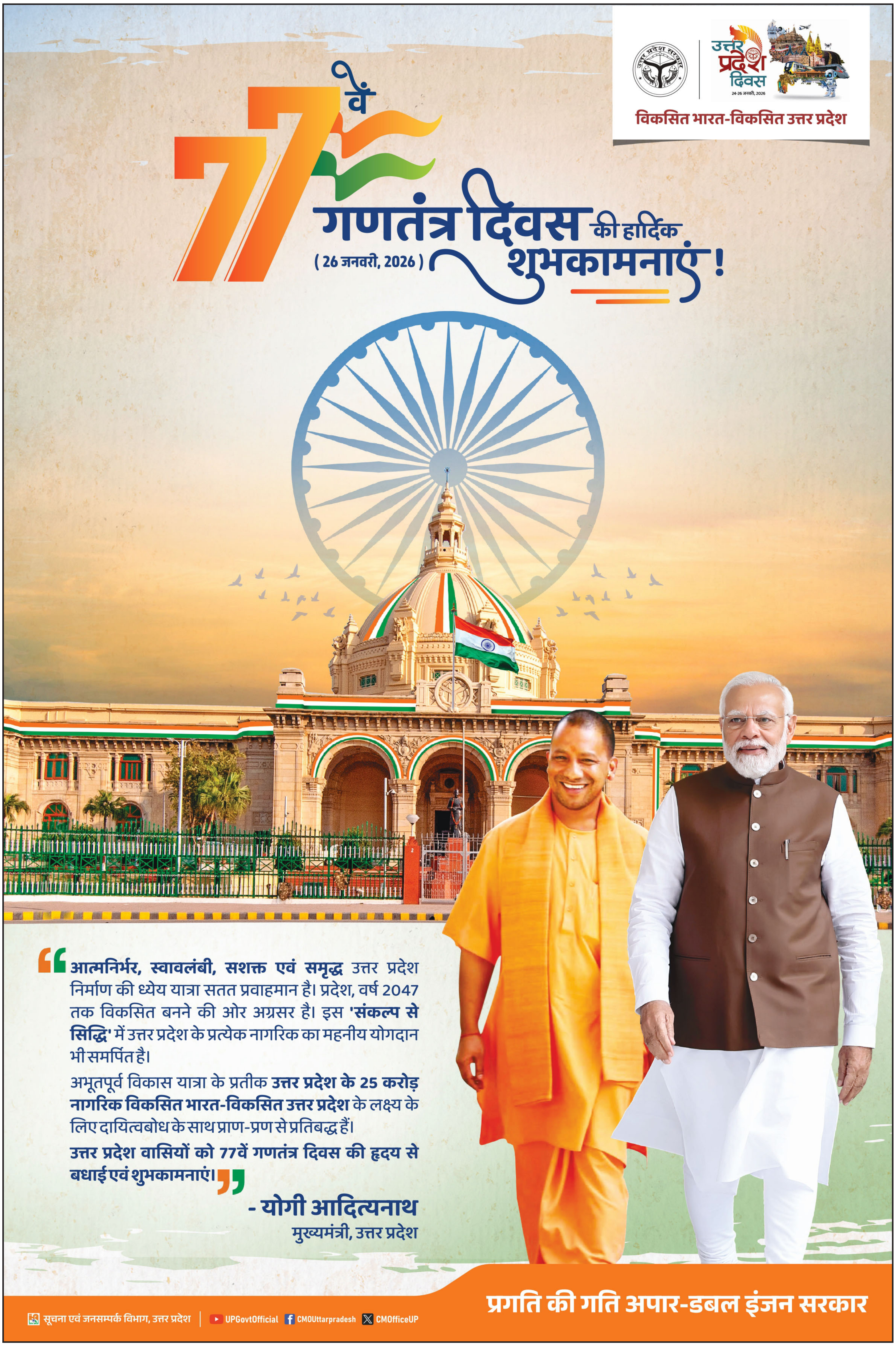

उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश दिवस
24-26 जनवरी, 2026
विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश
77वें
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
(26 जनवरी, 2026)
प्रगति की गति अपार-डबल इंजन सरकार

"**आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, सशक्त एवं समृद्ध** उत्तर प्रदेश निर्माण की ध्येय यात्रा सतत प्रवाहमान है। प्रदेश, वर्ष 2047 तक विकसित बनने की ओर अग्रसर है। इस **'संकल्प से सिद्धि'** में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का महनीय योगदान भी समर्पित है।

अभूतपूर्व विकास यात्रा के प्रतीक **उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश** के लक्ष्य के लिए दायित्वबोध के साथ प्राण-प्रण से प्रतिबद्ध हैं।

उत्तर प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं।"

- योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश | UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

भारत और यूरोप ने महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की

नई दिल्ली। भारत और यूरोप ने मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की जिसे अबतक का सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है। यह समझौता अस्थिर वैश्विक माहौल और अमेरिका की शुल्क नीति के कारण उत्पन्न व्यापार व्यवधानों की पृष्ठभूमि में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने २७ देशों के यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं उर्सुला वन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा के साथ वार्ता करने के बाद कहा कि आज भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) यूरोपीय संघ के साथ संपन्न किया है। मोदी ने बयान में कहा, श्श यह केवल एक व्यापार समझौता नहीं है। यह साझा समृद्धि के लिए एक नया खाका है।श्श दोनों पक्षों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते और आवागमन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत–यूरोपीय संघ की साझेदारी से दुनिया को फायदा होगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कोस्टा ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, सुरक्षा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों में एक 'नया अध्याय' शुरू किया है। उन्होंने कहा, ''व्यापार समझौते नियम–आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं और साझा समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आज का मुक्त व्यापार समझौता ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी समझौतों में से एक है।'' वॉन डेर लेयेन ने कहा,'' हमने 'मदर ऑफ ऑल द डील्स' (अब तक का सबसे बड़ा समझौता) किया है।''

बहुप्रतीक्षित भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता एक अत्यधिक महत्वपूर्ण समझौता है जिसे 'मदर ऑफ ऑल द डील्स' यानी अबतक का सबसे बड़ा समझौता कहा जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों की समग्र दिशा में महत्वपूर्ण विस्तार होने की उम्मीद है क्योंकि यह विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोलेगा। शिखर सम्मेलन के बाद, दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता के समापन की औपचारिक घोषणा करने के लिए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में कम से कम छह महीने लग सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा इसकी कानूनी जांच आवश्यक होगी। यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पहली बार २००७ में शुरू की थी, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण २०१३ में बातचीत स्थगित कर दी गई थी। जून २०२२ में फिर से बातचीत शुरू की गई। यूरोपीय संघ एक समूह के रूप में, वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष २०२४–२५ में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग १३६ अरब अमेरिकी डॉलर का था। इसमें निर्यात करीब ७६ अरब अमेरिकी डॉलर और आयात ६० अरब अमेरिकी डॉलर का था। शिखर सम्मेलन में मुख्य तौर पर व्यापार, रक्षा एवं सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और नियम–आधारित वैश्विक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ २००४ से रणनीतिक साझेदार रहे हैं। प्रस्तावित सुरक्षा एवं रक्षा साझेदारी (एसडीपी) दोनों पक्षों के बीच गहन रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगी।

गणतंत्र दिवस २०२६ के उपलक्ष्य पर ९८२ कर्मियों को मिला वीरता और सेवा सम्मान

नई दिल्ली। देश आज अपना ७७ वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बीच गणतंत्र दिवस २०२६ के उपलक्ष्य में पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस (एचजीएंडसीडी) तथा 'करेक्शनल सर्विसेज' (सुधारात्मक सेवा) के ९८२ कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदकों से नवाजा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें से १२५ पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया। गृह मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि इनमें से १२५ पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा जिनमें १२१ पुलिस सेवा के और चार अग्निशमन सेवा के हैं। वीरता पदक पाने वाले १२१ पुलिसकर्मियों में से ३५ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, ४५ जम्मू कश्मीर के, पांच पूर्वोत्तर के और ४० शेष देश के हैं। सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के ३३ पुलिसकर्मियों, महाराष्ट्र के ३१, उत्तर प्रदेश के १८, दिल्ली के १४, मणिपुर के पांच, ओडिशा के चार, बिहार के तीन और तेलंगाना के एक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के १२, पुलिसकर्मी को वीरता पदक से नवाजा गया है। इसके अलावा १०१ पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से ८९ पुलिस सेवा, पांच अग्नि शमन सेवा, तीन नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड और २५ सुधारात्मक सेवा के हैं। विभिन्न सेवाओं के ७५६ पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया जायेगा। इनमें से ६६४ पुलिस सेवा, ३४ अग्नि शमन सेवा, ३३ नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड तथा २५ सुधारात्मक सेवा के हैं। वीरता पदक वीरता के दुर्लभ और बहादुरी के कार्यों के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें जान और माल की रक्षा करना, या अपराध रोकना या अपराधियों को गिरफ्तार करना शामिल है। इसमें होने वाले जोखिम का अनुमान संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक सेवा के दौरान विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए दिया जाता है। बयान के मुताबिक, वीरता पदक असाधारण बहादुरी और विशिष्ट वीरतापूर्ण काम के आधार पर जीवन और संपत्ति बचाने या अपराध को रोकने या फिर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए दिया जाता है। इसमें उठाए गए जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्वों और कर्तव्यों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (**PSM**), सेवा में विशेष रूप से विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। सराहनीय सेवा के लिए पदक (**MSM**) कर्तव्य के प्रति निष्ठा की विशेषता वाली मूल्यवान सेवा के लिए दिया जाता है।

बजट सत्र २०२६-२७ : सर्वदलीय बैठक संपन्न, किरेन रिजिजू बोले- सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नियम प्रक्रियाओं के तहत काम करती है और वह सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि बजट सत्र में हर चर्चा बजट पर ही केंद्रित होना चाहिए यह नियम कहता है। बजट सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। उसके बाद बजट पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य कई मुद्दे उठा सकते हैं क्योंकि अभिभाषण में सरकार को लेखाजोखा रखा जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हर बात सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ हंगाम करके अगर विपक्ष सदन को नहीं चलने देती है तो तकलीफ होती है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहती है लेकिन यह बजट सत्र है इसलिए इसमें बजट पर चर्चा करना इसे पास करना एक नियम है। हम लोग नियम से बाहर जाकर कोयी काम नहीं करते हैं। संविधान से देश चलता है कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करता है। रिजिजू ने कहा, ष्मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। पिछली बार सभी विपक्षी पार्टियों ने मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया था। हमने चुनाव सुधारों पर चर्चा की जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी शामिल था। चुनाव सुधार पर लोकसभा और राज्यसभा में लंबी चर्चा हुई थी जिसमें सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष अलग फिर से एसआईआर पर बहस या चर्चा चाहते हैं तो यह बेवजह होगा क्योंकि इस पर पहले ही पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है।'

गणतंत्र दिवस पर इरम एजुकेशनल सोसाइटी की भव्य झांकी

लखनऊ। २६ जनवरी २०२६ को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इरम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा "नया भारत आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत" की संकल्पना पर आधारित एक भव्य, आकर्षक एवं संदेशपरक झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इसी क्रम में झांकी की रूपरेखा और उद्देश्य को लेकर सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सोसाइटी के प्रबंधक खघ्वाजा बजमी यूनुस ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ख्वाजा बजमी यूनुस ने बताया कि यह झांकी आधुनिक भारत की निरंतर प्रगति, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र की बढ़ती शक्ति का सशक्त प्रतीक होगी। झांकी के अग्रभाग में भारत माता का दिव्य स्वरूप देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति की भावना को दर्शाएगा। वहीं, तेज रफ्तार मेट्रो रेल और वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत के उन्नत परिवहन तंत्र और मजबूत बुनियादी ढांचे की कहानी बयां करेंगी। झांकी में इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से भारत की वैज्ञानिक क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाया जाएगा। यह दृश्य वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती पहचान और वैज्ञानिक सामर्थ्य का प्रतीक होगा। इसके अतिरिक्त झांकी में "ऑपरेशन सिंदूर" को भी सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो देश की सुरक्षा, साहस और भारतीय सेना के शौर्य को दर्शाता है। इसके माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि भारत न केवल विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए हर स्तर पर पूरी तरह सक्षम और सजग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित गणमान्य नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बजमी यूनुस ने कहा कि इरम एजुकेशनल सोसाइटी शिक्षा के साथ–साथ राष्ट्रभक्ति, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह झांकी नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत करेगी। अंत में उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे २६ जनवरी को आयोजित होने वाली इस भव्य झांकी को देखने अवश्य आएं और गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय एकता, गौरव और उत्साह के साथ मनाएं।

नया भारत आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत
3
इरम एजुकेशनल सो

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आयोजित, 500 से अधिक लोगों को दिलाई गई मतदाता शपथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में १६वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजधानी लखनऊ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करते हुए उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत, राज्य स्वीप आइकन सुश्री सुधा सिंह एवं सुश्री अनुष्का चौबे, तथा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाख जी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लगभग ५०० अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को मतदाता शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर "निर्वाचन के बढ़ते कदम" थीम पर 'जर्नी ऑफ इलेक्शन' प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया में समय–समय पर हुए महत्वपूर्ण बदलावों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महिला एवं युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ७५ बूथ लेवल अधिकारियों, ७५ बीएलओ सुपरवाइजर, १८ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) तथा ६ जिला निर्वाचन अधिकारियों (एटा, बाराबंकी, औरैया, शामली, महोबा एवं फतेहपुर) को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त १८ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले १५ नए युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए गए, जबकि ५ महिला मतदाताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम "मेरा भारत, मेरा वोट" है। उन्होंने बताया कि २५ जनवरी १९५० को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तथा मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष २०११ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में यह अभियान २२ वर्षों बाद व्यापक स्तर पर संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत घर–घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ६ जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल १२ करोड़ ५५ लाख ५६ हजार २५ मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब भी कुछ पात्र नागरिक, विशेष रूप से महिलाएं एवं १८ से २० वर्ष आयु वर्ग के युवा, मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस दिशा में ११ एवं १८ जनवरी को विशेष अभियान चलाए गए, जिनके माध्यम से ७ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगामी ३१ जनवरी को पुनः विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम पूर्व में सूची में था लेकिन वर्तमान में किसी कारणवश हट गया है, वे फॉर्म–०६ एवं घोषणा पत्र भरकर पुनः अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। बीएलओ की भूमिका की सराहना करते हुए श्री रिणवा ने कहा कि तकनीक के माध्यम से अब उनके कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे उत्तर प्रदेश सीईओ की वेबसाइट, अवजमते.मबप.हवअ.पद, ईसीआई नेट ऐप अथवा १९५० हेल्पलाइन के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचें। साथ ही राजनीतिक दलों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी पात्र नागरिकों के नाम दर्ज कराने में सहयोग की अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ एवं उनकी टीमों को प्रोत्साहन स्वरूप विदेशी अध्ययन भ्रमण पर भेजे जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस
NATIONAL VOTERS' DAY
25th JANUARY, 2026
मेरा भारत, मेरा वोट
मुख्य अतिथि

सरोजिनी नगर में 'हमारा आंगन, हमारे बच्चे' कार्यक्रम का भव्य आयोजन, ६५ बच्चों को किया गया सम्मानित

लखनऊ। जनपद लखनऊ के विकासखंड सरोजिनी नगर में शुक्रवार को 'हमारा आंगन, हमारे बच्चे' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संचालित ६८ को–लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सुपरवाइजर, बच्चे एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी सरोजिनी नगर श्री आर.पी. यादव एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री शैलेंद्र सिंह रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अभिभावकों, आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं शिक्षकों के समक्ष बाल वाटिका कार्यक्रम तथा प्री–प्राइमरी स्तर से शिक्षा आरंभ करने की व्यवस्था पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। अतिथियों द्वारा प्री–प्राइमरी शिक्षा के महत्व और बच्चों के सर्वांगीण विकास में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अभिभावकों को जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में १३ न्याय पंचायतों से चयनित ६५ बच्चों को उतेंष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जिससे बच्चों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर विकास स्तरीय बाल वाटिका नोडल एआरपी प्रतिमा मिश्रा, पूर्व एआरपी उदय प्रताप सिंह, शुचिता त्रिपाठी सहित सभी नोडल शिक्षक संकुल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी एवं विद्यालयी शिक्षा के बेहतर समन्वय के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना रहा।

औचक निरीक्षण में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की सख्ती : फर्जी हाजिरी पर फटकार, घर-घर सत्यापन का आदेश

लखीमपुर खीरी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंगलवार को संविलियन विद्यालय सदर का औचक निरीक्षण कर फर्जी हाजिरी की पोल खोल दी। रजिस्टर में बच्चों की उपस्थिति अच्छी दिख रही थी, लेकिन कक्षाओं में बच्चों की संख्या उससे आधी भी नहीं थी। विद्यालय में पंजीकृत १९६ छात्र–छात्राओं में से शिक्षामित्र अर्चना ने १०६ बच्चों की उपस्थिति अंकित कराई थी, जबकि डीएम के निर्देश पर भौतिक गिनती में केवल ४३ छात्र–छात्राएं ही उपस्थित पाए गए। डीएम ने मौके पर बीईओ को संबंधित शिक्षामित्र से तुरंत स्पष्टीकरण लेने और उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपस्थिति के अंतर को लेकर मध्यान्ह भोजन योजना पर भी सवाल उठे। डीएम ने बच्चों की अंकित संख्या के अनुसार कन्वर्जन कास्ट का परीक्षण कराने और नामित एनजीओ के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, लखीमपुर को आदेश दिया कि पिछले एक माह में उपस्थित दिखाए गए हर बच्चे का उसके आवास से फिजिकल सत्यापन कराया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे विद्यालय में नियमित रूप से आ रहे हैं या अन्यत्र पंजीकरण करा रखा है। डीएम ने कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, परिसर व शौचालयों में साफ–सफाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। वहीं, प्राथमिक विद्यालय राजापुर के निरीक्षण में डीएम ने संतोषजनक व्यवस्था पाई। यहां विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और रजिस्टर की संख्या मेल खा रही थी। शिक्षकों द्वारा कक्षा संचालन नियमित और अनुशासित तरीके से किया जा रहा था। डीएम ने देखा कि कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था थी, बच्चों के बैठने और शिक्षण के लिए समुचित व्यवस्था थी। विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना भी सुचारू रूप से चल रही थी और बच्चों को भोजन समय पर और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था।

अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चला बुलडोजर, अधिकारी और पुलिस बल मौजूद

कानपुर। अवैध निर्माण और अनधिकृत विकास कार्यों के विरुद्ध कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा प्रवर्तन जोन–१बी के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के निर्देशन में मंगलवार को विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई सम्पन्न हुई। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन टीम के अधिकारी, अभियंता और थाना बिठूर का पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। प्रवर्तन टीम ने मटका चौराहे से जंगल वाटर पार्क मोड़ पर, भगवान बुद्ध आश्रम के पीछे लगभग ४.५ बीघा क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। बिना कानपुर विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत कराए की जा रही इस प्लाटिंग में निर्मित सड़क, नाला, बाउंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्री गेट सहित सभी संरचनाओं को तीन जेसीबी मशीनों की मदद से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा सिंहपुर कछार क्षेत्र में लगभग ५.५ बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति के किए गए निर्माण को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २८(क) के तहत सील कर दिया गया। यह परिसर अभिषेक कटियार, सुशील कटियार एवं अन्य के स्वामित्व का बताया गया है।

खाद्य वितरण में शोषण का आरोप किसानों का गुस्सा फूटा हुआ हंगामा

(हरिशंकर मिश्र)

लखीमपुर खीरी। विकास खंड बिजुआ अंतर्गत साधन सहकारी समिति बसतौली में आज यूरिया वितरण को लेकर खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का धैर्य जवाब दे गया और वहां खाद वितरण को लेकर जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया और वितरण प्रक्रिया के दौरान अव्यवस्था फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार मामले ने तब और भी तूल पकड़ लिया जब समिति के कर्मचारियों ने एक किसान पर गोदाम से जबरन यूरिया की बोरी उठाने का गंभीर आरोप लगाया। घंटों चले इस हंगामे के कारण समिति पर अफरा–तफरी का माहौल बना रहा और कामकाज ठप सा हो गया। ज्ञात हो कि इस समय में फसलों में यूरिया खाद की भारी मांग चल रही है, जिसके चलते सरकारी समितियों पर किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। इसी क्रम में बसतौली समिति पर भी सुबह से ही सैकड़ों किसान खाद लेने के लिए आए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यूरिया का स्टॉक कम होने का रोना सुनकर और वितरण की गति धीमी होने के कारण किसान आक्रोशित थे। किसानों का आरोप है कि उन्हें घंटों इंतजार कराया जा रहा है और खाद की कालाबाजारी की आशंका बनी रहती है। चल रहे हंगामे के दौरान समिति कर्मचारियों ने एक किसान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ का फायदा उठाकर एक किसान गोदाम के भीतर घुस गया और उसने जबरन यूरिया की बोरी उठाने की कोशिश की। कर्मचारियों का कहना है कि जब उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने बदतमीजी करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली जबकि दूसरी ओर किसानों का कहना है कि कर्मचारी चहेतों को खाद दे रहते हैं और आम किसान लाइन में खड़ा रह जाता है। इसी गहमागहमी के बीच एक किसान ने अपना हक मांगते हुए खाद की बोरी उठाई, जिसे कर्मचारियों ने ‘लूट’ और ‘जबरन’ उठाने का नाम दे दिया। किसानों का यह भी आरोप है कि इस समिति का सचिव व अन्य कुछ कर्मी काफी भ्रष्ट हैं और किसानों का शोषण करने में माहिर हैं जिसके चलते आए दिन छोटी–मोटी नोक झोक तो वैसे भी किसानों से होती रहती है। विवाद होने के बाद समिति के कर्मचारियों ने वितरण कार्य रोक दिया, जिससे कतार में खड़े अन्य किसानों का गुस्सा और बढ़ गया और मौके पर मौजूद किसानों ने समिति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और सहकारिता विभाग के अधिकारी सक्रिय हुए। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और दोनों पक्षों को शांत कराया। आए दिन समितियों पर हो रहे हंगामों ने सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि खाद वितरण में पारदर्शिता क्यों नहीं अपनाई जा रही? क्या कर्मचारियों की मिलीभगत से खाद ऊंचे दामों पर निजी दुकानों तक पहुँचाई जा रही है? किसानों के लिए बने इन केंद्रों पर किसान अपमानित क्यों हो रहे हैं? समिति के कर्मचारी इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों और स्थानीय पुलिस से करने की बात कह रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यदि गोदाम से इस तरह जबरन खाद उठाई जाएगी, तो वे सुरक्षा के अभाव में काम नहीं कर पाएंगे। वहीं किसान संगठनों के स्थानीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों को सुचारू और सम्मानजनक तरीके से यूरिया खाद आदि नहीं दिया जाता है तो वे इसके लिए बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। समाचार लिखने तक मिली जानकारी के अनुसार बसतौली समिति पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस बल की निगरानी में वितरण प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बी.पी.एस.स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

लखीमपुर खीरी। बी.पी.एस.पब्लिक स्कूल मेला रोड में गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास गरिमा और राष्ट्रभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती प्रमोदिनी शुक्ला, प्रधानाचार्य श्रीमती नीलम अवस्थी द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। राष्ट्रध्वज को सलामी देते हुए सभी ने राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत हाउस वाइज मार्च पास्ट ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। अनुशासन एकता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण इस मार्च पास्ट में छात्रों ने राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओत–प्रोत कविताएं,भाषण एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिसमें संविधान के महत्व, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव–विभोर कर दिया। इस अवसर पर इन्वेस्ट टीचर इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन भी अत्यंत गरिमामय एवं प्रेरणादायी वातावरण में किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित विद्यालय कैबिनेट को विधिवत दायित्व सौंप गए विद्यालय कप्तान, उप कप्तान, हाउस कैप्टन एवं प्रीफेक्ट्स को बैज एवं सैश प्रदान कर उनके दायित्वों की औपचारिक घोषणा की गई। नवनिर्वाचित छात्र–नेतृत्व ने विद्यालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन का पालन करने तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य महोदया ने अपने संबोधन में संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे एक जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि अनुशासन, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों का पालन ही सशक्त भारत की नींव है। ‘वंदे मातरम्’ की १५०वी वर्षगांठ पर उसके शब्दों के अर्थों को सक्रिय रूप से साकार करें। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति के नारों और मिठाई वितरण के साथ हुआ। संपूर्ण वातावरण देशप्रेम, उत्साह और गर्व की भावना से ओत–प्रोत रहा।

B.P.S. Public School

UP की आबकारी नीति बनी राष्ट्रीय मॉडल, कई राज्यों के अधिकारियों ने किया अध्ययन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी और पारदर्शी आबकारी नीति ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई है। लगातार रिकॉर्ड वृद्धि के साथ राज्य की आबकारी राजस्व व्यवस्था अब एक राष्ट्रीय सफलता मॉडल के रूप में उभर चुकी है, जिसे अन्य राज्य अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश समेत छह से अधिक राज्यों के आबकारी आयुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश पहुंचकर राज्य की आबकारी नीति का गहन अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान अधिकारियों ने नीति निर्माण, ई–गवर्नेंस, लाइसेंस प्रक्रिया और राजस्व वृद्धि में सहायक निगरानी तंत्र पर विस्तृत चर्चा की। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों ने उत्तर प्रदेश की व्यावहारिक और राजस्व–केंद्रित आबकारी नीति की सराहना की है और इसे अपने राज्यों में लागू करने पर विचार कर रहे हैं। दौरे के दौरान विभिन्न राज्यों के अधिकारियों ने प्रदेश की डिस्टिलरी और शराब दुकानों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उत्पादन से लेकर बिक्री तक की निगरानी व्यवस्था को समझा और यह भी देखा कि किस तरह अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, ई–लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन, बारकोडिंग और स्टॉक प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। अधिकारियों का कहना था कि इन तकनीकी उपायों से न केवल आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों के आबकारी विभागों के अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश आकर नीति, प्रशासनिक व्यवस्था और तकनीकी नवाचारों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘अन्य राज्यों के अधिकारी हमारी आबकारी नीति की कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं ताकि वे अपने–अपने राज्यों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू कर सकें।’

बरेली में बवालः निलंबित मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की मांग- राष्ट्रपति शासन लागू करो

बरेली। मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए निलंबित बरेली नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन पर उत्पीड़न और जाति आधारित दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के आचरण पर सवाल उठाए और व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं जिला मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि उन्हें कल रात किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने के कारण गाली दे रहा है, और वह व्यक्ति किस विचारधारा का है? संवैधानिक प्रक्रियाओं के टूटने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आम जनता सरकार के खिलाफ हो गई है। यह विरोध प्रदर्शन अग्निहोत्री के नगर मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के शिविर कार्यालय में रात भर बंधक बनाकर रखने की सुनियोजित साजिश रची गई थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया था। जिला मजिस्ट्रेट के शिविर कार्यालय में फोन आया कि इस ‘पंडित’ को पूरी रात वहीं बैठाकर रखा जाए और उसे कहीं जाने न दिया जाए। अग्निहोत्री ने बताया कि जब उन्हें लगा कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाया जा रहा है, तो उन्होंने बार एसोसिएशन और मीडिया को सूचित किया। उन्होंने कहा, ‘जब उन्हें पता चला कि मीडिया को मुझे बंधक बनाने की योजना की जानकारी है, तो मुझे जाने दिया गया।’ उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह घटना उन्हें बयान जारी करने के लिए मजबूर करने और फिर अलग आधार पर निलंबित करने की साजिश का हिस्सा थी। जांच की मांग करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि फोन पर हुई बातचीत और उनके निलंबन से जुड़े हालातों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम निलंबन आदेश के संबंध में अदालत में अपील करेंगे और जल्द ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे। इससे पहले, अग्निहोत्री ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश में ‘ब्राह्मण विरोधी अभियान’ चल रहा है और उन्होंने ब्राह्मणों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटनाओं का हवाला दिया, जिनमें प्रयागराज में माघ मेले के दौरान हुई घटनाएं भी शामिल हैं। अधिकारियों ने अभी तक उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

लखनऊः बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में धूमधाम से मना ७७वां गणतंत्र दिवस, बच्चों की देशभक्ति प्रस्तुतियों ने मोहा मन

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित नगर क्षेत्र के जोन–एक स्थित बेसिक विद्यालय अलीनगर सुनहरा में ७७वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पाण्डेय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के उपरांत अपने संबोधन में प्रभारी प्रधानाध्यापक ने सरकार द्वारा विद्यालयों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि २६ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे महान मूल्यों की सीख देता है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप ही देश का भविष्य हैं। शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के माध्यम से आप भारत को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक बनना ही सच्चा देशप्रेम है। इस अवसर पर बच्चों को संविधान के सम्मान और कर्तव्यों के ईमानदार पालन की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, कविताएँ एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उपस्थित शिक्षकों, अभिभावकों एवं अतिथियों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी–भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के समापन पर सभी विद्यार्थियों को मिष्ठान वितरित किया गया, जबकि उपस्थित अभिभावकों एवं अतिथियों और शिक्षक, प्रशिक्षुओं का सूक्ष्म जलपान कराकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर डीएलएड प्रशिक्षु, शिक्षकगण, अभिभावक एवं अन्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

HAPPY REPUBLIC DAY
Teachers

मुख्य सचिव और डीजीपी ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्णा ने सोमवार को ७७वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलग–अलग स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गोयल ने अपने सरकारी आवास परिसर में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम में अपना सबकुछ न्योछावर करने वालों को श्रद्धांजलि दी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ध्वजारोहण के बाद मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ″इस यात्रा में प्रत्येक नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और समाज के हर वर्ग को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा।″ डीजीपी राजीव कृष्ण ने तिलक मार्ग पर स्थित अपने आवास व शिविर कार्यालय और गोमती नगर एक्सटेंशन में स्थित पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभा को संबोधित करते हुए कृष्णा ने कहा कि हर नागरिक को समान सुरक्षा मिलना, सुनवाई का समान अवसर मिलना कानून के राज की आत्मा है।

कॉलेज के पास नवजात बच्ची का शव मिला

देवरिया । उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक निजी कॉलेज के पास झाड़ियों में सोमवार सुबह एक दिन की बच्ची का शव मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पोस्टम र्टम के दौरान बच्ची के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। देवरिया सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि शव संत विनोबा पीजी कॉलेज के पास झाड़ियों से मिला।

‘बॉर्डर 2’ ने 100 करोड़ पार कर रचा इतिहास

मुम्बई। सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर २’ ने रिलीज के पहले दिन से ही रफ्तार पकड़ी हुई है। सिर्फ तीन दिनों में फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन १२१ करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। देशभक्ति, जज्बे और बड़े सितारों की दमदार मौजूदगी ने इस फिल्म को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पर नजर डालें तो ‘बॉर्डर २’ ने बेहद शानदार शुरुआत की। पहले दिन फिल्म ने करीब ३० करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन इसमें और तेजी आई और कलेक्शन बढ़कर ३६.५ करोड़ रुपए तक पहुंच गया। असली धमाका तीसरे दिन देखने को मिला, जब इस वॉर ड्रामा ने करीब ५४.५ करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। इन आंकड़ों के साथ ‘बॉर्डर २’ ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यह महज तीन दिनों में सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इसने ‘जाट’ और ‘गदरः एक प्रेम कथा’ जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। साल २०२५ की फिल्मों की बात करें तो ‘बॉर्डर २’ ने ओपनिंग वीकेंड पर कई बड़ी फिल्मों को मात दे दी है। इसने ‘धुरंधर’, ‘थामा’, ‘हाउसफुल ५’, ‘सिकंदर’ और ‘सैयारा’ जैसी फिल्मों के शुरुआती वीकेंड कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। तीसरे दिन की कमाई के मामले में भी ‘बॉर्डर २’ ने इतिहास रच दिया। इसने ‘दंगल’, ‘बाहुबली २’, ‘आरआरआर’, ‘केजीएफ २’ और ‘गदर २’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के तीसरे दिन के कलेक्शन रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे कलाकार हैं। इसके निर्माता गुलशन कुमार और टी–सीरीज हैं। फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं। ‘बॉर्डर २’ १९९७ में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो १९७१ के भारत–पाक युद्ध पर आधारित थी। नई फिल्म भी उसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसे नए दौर की कहानी और भावनाओं के साथ पेश किया गया है।

GULSHAN KUMAR, T-SERIES & JP FILMS PRESENT
A T-SERIES FILMS & JP FILMS PRODUCTION
BORDER 2
IN CINEMAS

मुश्किल किरदार निभाकर सामान्य जीवन में लौटना ‘री–एंट्री’ जैसा, केट विंसलेट

मुम्बई। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री केट विंसलेट का कहना है कि परदे पर गहरे और मुश्किल किरदार निभाने के बाद उन्हें अपनी असली जिंदगी में लौटने में काफी मुश्किल होती है। अ स्कर पुरस्कार जीत चुकी केट विंसलेट ने ‘लेसन्स फ्र म अवर मदर्स’ नाम के पॉडकास्ट में कहा कि एक कलाकार के तौर वह कुछ अनुभवों के बारे में बहुत कम बात करती हैं, क्योंकि यह बात उन्हें खुद भी कुछ ज्यादा निजी लगती है। उन्होंने बताया कि जब कोई अभिनेता बहुत कठिन किरदार निभाता है, तो उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। उन्होंने अपनी वेब सीरीज ‘मेयर ऑफ ईस्टटाउन’ का जिक्र करते हुए कहा कि इस भूमिका ने उन्हें अंदर तक थका दिया था। केट ने बताया ऐसे किरदार निभाने के बाद उन्हें जिंदगी में फिर से ″री–एंट्री″ करनी पड़ती हैय यानी दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में वापस लौटना। इसका मतलब है फिर से अपनी दोस्ती निभाना, परिवार की दिनचर्या में लौटना और उस किरदार को पीछे छोड़ देना, जिसे उन्होंने लंबे समय तक जिया हो। उन्होंने कहा कि किसी किरदार को अपने अंदर से पूरी तरह अलग होने में वक्त लगता है, खासकर तब, जब टेलीविजन के लिए वह भूमिका लंबे समय तक निभाई गई हो। अभिनेत्री ने यह भी बताया कि साल २०२१ में आई ‘मेयर ऑफ ईस्टटाउन’ में काम करने के बाद उन्हें पेशेवर मदद लेनी पड़ी। इस सीरीज की शूटिंग कोरोना महामारी की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उन्होंने बताया कि यह शूटिंग छह महीने में पूरी होनी थी, लेकिन महामारी के कारण काम रुक गया और फिर जब दोबारा शुरू हुआ, तो बचे हुए पांच हफ्ते बढ़कर दस हफ्ते हो गए। केट ने याद करते हुए कहा कि अंत तक वह उस किरदार को एक साल से भी ज्यादा समय तक निभा चुकी थीं। इसका असर उनके मानसिक संतुलन पर पड़ा और उन्हें लगा कि वह खुद से दूर होती जा रही हैं।

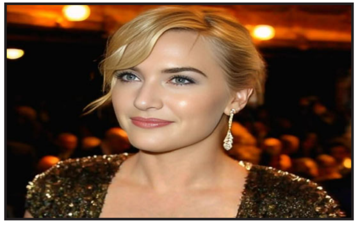

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विघिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक